जोसेफ जॉन पीटर सैंडी

बनाम

वेरोनिका थॉमस राजकुमार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2178-2179 /2004 आदि)

मार्च 12, 2013

[डॉ. बी.एस. चौहान और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे.जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963:

एस. धारा 26 निपटान कार्यों के सुधार के लिए मुकदमा - आयोजित: अपीलकर्ता सुधार के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता था निपटान विलेख, क्योंकि इसकी समझ में कोई गलती नहीं थी या पार्टियों द्वारा निष्पादन यह केवल के पिता था। पक्ष जो विलेख में सुधार की मांग कर सकते थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया, न ही उनसे पूछताछ की गई, यद्यपि मुकदमा संस्थित होने के समय वह अभी भी जीवित था - प्रतिवादी संख्या के रूप में एक कथित सुधार में कोई पक्ष नहीं था विलेख, वह इसके द्वारा बाध्य नहीं थी - इसके अलावा, ज्ञापन वादी द्वारा जिस समझौते पर भरोसा किया गया था, उसे साबित नहीं किया गया है - साक्ष्य प्रमाण का दायित्व।

अनुबंध अधिनियम, 1872:एस. 16 अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध धारित: उच्च एफ कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह अनुचित मामला

था कथित दस्तावेज़ को निष्पादित करने की तिथि पर प्रभाव, यानी समझौता ज्ञापन, प्रतिवादी संख्या। 1 था वह अस्वस्थ थी और अपने पिता और भाई पर निर्भर थी उसकी शादी तय करने और भरण-पोषण के लिएवह कर रही है ने तर्क दिया कि वादी अपनी वसीयत पर हावी होने की स्थिति में थी, कथित दस्तावेज़ को अतार्किक बताया गया - उक्त दस्तावेज़ संदेह के घेरे में था और अस्पष्टीकृत परिस्थितियाँ।

अपीलकर्ता के पिता और प्रतिवादी सं. 1 27.8.1981 को दो पंजीकृत निपटान विलेख निष्पादित किये मकान नंबर 23 को अपनी बेटी के नाम पर स्थानांतरित करना (प्रतिवादी संख्या 1) और मकान संख्या 22 उसके नाम पर बेटा (अपीलकर्ता). अपीलकर्ता ने O.S.No दायर किया। 6331 का 1983 दिनांक 12.9.1983 को प्रतिवादी/बी को निर्देश जारी करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, सुधार विलेख निष्पादित करने के लिए और इसके अलावा उसे इसमें हस्तक्षेप करने से रोका जाए वाद संपत्ति पर अपीलकर्ता का कब्ज़ा. यह था वादी-अपीलकर्ता का मामला यह है कि समझौते के बाद विलेख दिनांक 27.8.1981, पार्टियों के पिता को एहसास हुआ वो मकान नंबर 23 जो बेटी को दिया था. उसे और मकान नंबर 22 को दिया जाना चाहिए था बेटी। इस प्रकार, पार्टियों को वास्तविक प्रभाव देना होगा उनके पिता ने इरादे से विनिमय करने का निर्णय लिया उन्हें संपत्तियां दी गईं, और इसके अलावा, ने उसे विनिमय करने के लिए एक समझौता विलेख निष्पादित किया 1.6.1982 (एक्सटेंशन ए-3), लेकिन प्रतिवादी नं. 1 देने

में असफल रहा उसी पर प्रभाव. मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान, कहा गया कि निपटानकर्ता और अपीलकर्ता ने एक निष्पादित किया है 8.10.1983 को सुधार विलेख (एक्सट.ए-6) जिसके द्वारा ई दरवाज़ा नंबर 23 में संपत्ति अपीलकर्ता को दी गई थी। उक्त विलेख पर दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। प्रतिवादी नंबर१ प्रतिवादी ने मुकदमा ओ.एस. दायर किया 1984 की संख्या 415 के लिए घोषणा कि समझौता दिनांक 1.6.1982 (एक्सटी.ए-3), एक अपंजीकृत दस्तावेज़, अशक्त और शून्य था, एक होने के नाते जाली दस्तावेज़, और वह, अनुचित प्रभाव में, एफ कोरे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के मुकदमे पर फैसला सुनाया और खारिज कर दिया प्रतिवादी नंबर 1 का. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी दोनों अपीलें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गईं।

न्यायालय,नेअपीलों को खारिज करते हुए,

आयोजित: 1-.1. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 26 इसका अनुप्रयोग सीमित है और यह केवल वहीं लागू होता है याचना की जाती है और साबित किया जाता है कि धोखाधड़ी या पारस्परिक माध्यम से पार्टियों की गलती, पार्टियों की असली मंशा है किसी उपकरण के संबंध में व्यक्त नहीं किया गया। ऐसा सुधार की अनुमति केवल संबंधित पक्षों द्वारा ही है साधन और किसी अन्य द्वारा नहीं। [पैरा 7] [378-डी-ई]

ब सुभद्रा एवं अन्य। वी. थैंकम, 2010 (8) एससीआर 299 = एआईआर 2010 एससी 3031; कामताका राज्य और अन्य। वी. के.के. मोहनदास और आदि, 2007 (8) एससीआर 697 = एआईआर 2007 एससी 2917 पर भरोसा किया गया।

1.2. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या के रूप में 1 नहीं था दस्तावेज़ एक्सटेंशन ए-6 का एक पक्ष, वह इसके लिए बाध्य नहीं थी। यह. इसके अलावा, अपीलकर्ता मुकदमा दायर नहीं कर सका निपटान विलेख का सुधार, क्योंकि कोई गलती नहीं थी पार्टियों द्वारा समझ या निष्पादन में। वह था केवल पार्टियों के पिता जो मांग सकते थे विलेख का सुधार, लेकिन न तो उसे पक्षकार बनाया गया, न ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष उससे पूछताछ की गई, हालांकि वह अभी भी था मुकदमा संस्थित होने के समय जीवित था। फिर भी अपीलकर्ता गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा दस्तावेज़ एक्सटेंशन.ए-3. [पैरा 4] [377-सी-डी]

1.3. समझौता पत्र द्वारा इसमें कोई विवाद नहीं है दिनांक 27.8.1981 को पार्टियों के पिता ने सदन दिया था क्रमांक 23 जिसका माप 2413 वर्ग है। फ़ुट. बेटी को - प्रतिवादी संख्या 1 और मकान संख्या 22 जिसकी माप 730 वर्ग है। पुत्र को अपील अपीलकर्ता, साक्ष्य देने वाला कोई भी गवाह नहीं एफ से इन दस्तावेजों की जांच दोनों में से किसी एक द्वारा की गई थी पार्टियों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पार्टियों के पिता के पास था संपत्तियों के संबंध में कोई इरादा व्यक्त किया उनके पहले। एक्सटेंशन ए-6

दिनांक 28.10.1983 एक अपंजीकृत वह दस्तावेज़ जिसके द्वारा पिता ने अपनी वसीयत व्यक्त की थी जी हाउस नंबर 23 अपीलकर्ता के बेटे को दिया जाना चाहिए एक्सटेंशन.ए A1 और A2 के बाद। अपीलार्थी के पास है प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच की गई लेकिन उच्च प्रतिवादी के रूप में न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा नंबर 1 दस्तावेज़ का पक्षकार नहीं था, इसका कोई प्रभाव नहीं है, कानून में जो भी हो, मामले पर। [पैरा 20] [384-डी-एफ]

1.4. समझौता ज्ञापन दिनांक में 1.6.1982 में कहा गया है कि समझौता विलेख में गलतियाँ हुईं पिता द्वारा बनाई गई, पार्टियों की खोज की गई है केवल मई 1982 के अंतिम सप्ताह में, पार्टियों ने त्रुटि को सुधारने का निर्णय लिया और उस उद्देश्य के लिए, उन्होंने को आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित और पंजीकृत करेगा गलती सुधारो. इस प्रकार, दस्तावेज़ उदा.ए-3 नहीं हो सकता इसे "विनिमय करने के समझौते" के रूप में पढ़ें। इसे केवल पढ़ा जा सकता है एक सुधार विलेख के रूप में, जो केवल किया जा सकता था बंदोबस्तकर्ता द्वारा, न कि प्रतिस्पर्धी पार्टियों द्वारा। धारण करने वाली संपत्तियों के संबंधित क्षेत्र पर विचार करते हुए संख्य 22 और 23 अनुबंध निश्चित रूप से आयोजित किया जा सकता है "अचेतन"~ [पैरा 20 और 27(viii)] [384-जी-एच; 385-ए; 388-एफ]

2.1. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 में प्रावधान है कि एक अनुबंध को "अनुचित प्रभाव" से प्रेरित माना जाता है जहां पार्टियों के बीच

मौजूद संबंध हैं ऐसा कि कोई एक पक्ष हावी होने की स्थिति में हो दूसरे की इच्छा, और उस स्थिति का उपयोग एक प्राप्त करने के लिए करता है दूसरे पर अनुचित लाभ। [पैरा 7) [378-एफ-जी]

बिशुनदेव नारायण और अन्य। बनाम सेओगेनी राय और जगेमथ 1951 एससीआर 548 = एआईआर 1951 एससी 280; लाडली प्रसाद जयसवाल वी. द कर्ण/डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, कर्ण/ एवं अन्य, 1964 एससीआर 270 = एआईआर 1963 एससी 1279; सुभाष चंद्र दास मुशीब बनाम गंगा प्रसाद दास मुशीब एवं अन्य, 1967 एफ एससीआर 331 = एआईआर 1967 एससी 878; अफ़सर शेख और अन्य बनाम सोलेमन बीबी और अन्य. 1976 (2) एससीआर 327 =एआईआर 1976 एससी 163 - विश्वसनीय पर।पूसाथुराई बनाम कन्नप्पा चेट्टियार, एआईआर 1920 पीसी 65 - जी करने के लिए भेजा।

2.2. मौजूदा मामले में हाई कोर्ट पहुंचे निष्कर्ष यह है कि यह अनुचित प्रभाव का मामला था कथित दस्तावेज़ Ext.A-3 को निष्पादित करने की तिथि,

प्रतिवादी नंबर 1 अविवाहित था और उस पर निर्भर था उसके पिता और भाई ने उसकी शादी तय करने के लिए और उसके लिए जीविका, और, इस प्रकार, वादी एक स्थिति में था उसकी इच्छा पर हावी होना. यह एक ऐसा मामला था, जिसमें, उसके बाद कुछ पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के हस्ताक्षर

प्राप्त करना कागजात, दस्तावेज़ लिखा गया था. इसके संबंध में दस्तावेज़, उच्च न्यायालय ने माना कि उक्त दस्तावेज़ ExlA-3 एक टाइप किया हुआ दस्तावेज़ है, इसमें शामिल होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम जिसने इसे लिखा था। यह आगे तर्क दिया कि उसमें प्रयुक्त भाषा से ऐसा पता चलता है इसका मसौदा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रकार, संपूर्ण दस्तावेज़ संदेह के घेरे में है और अस्पष्ट है परिस्थितियाँ। [पैरा 24) (386-बी-ई)

मदन मोहन सिंह एवं अन्य बनाम रजनी कांत एवं अन्य, 2010 डी (10) एससीआर 30 =एआईआर 2010 एससी 2933; बिहार राज्य एवं अन्य। वी राधा कृष्ण सिंह एवं अन्य, एआईआर 1983 एससी 684; एच.सिद्दीकी (मृत) एलआरएस द्वारा। वी. ए. रामलिंगम 2011 (5) एससीआर 587 =·एआईआर 2011 एससी 1492; लक्ष्मीबाई (मृत) तृ. Lrs. एवं अन्य वी. भगवन्तबुवा (मृत) तृ. एवं अन्य, जेटी 2013(2) एससी 362 - ई पर भरोसा किया.

हरि सिंह बनाम कन्हैया लाल 1999 सप्ल. (2) एससीआर 216= एआईआर 1999 एससी 3325 - संदर्भित।

2.3. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भले ही दस्तावेज़ एफ स्वीकार्य हो सकता है, फिर भी इसकी सामग्री को साबित करना होगा। वर्तमान मामले में, चूँकि अपीलकर्ता ने जाँच नहीं की न तो दस्तावेज़ के प्रमाणित गवाह,

न ही यह साबित कर दिया कि इसकी सामग्री में कोई दोष नहीं पाया जा सकता उच्च न्यायालय का निर्णय. किसी भी पार्टी के पास नहीं है जी ने दस्तावेज़ एक्सटेंशन-ए-3 को प्रमाणित करने वाले गवाह से पूछताछ की। ऐसा गवाह उसके आचरण को स्पष्ट कर सकता था पार्टियों और इस बात से अवगत कराया कि एक्सटेंशन किसने तैयार किया था। ए-3. ट्रायल कोर्ट ने यह तर्क दिया था, भले ही· अपीलकर्ता ने उदा.ए H 3 के प्रमाणित गवाह की जांच नहीं की, प्रतिवादी ऐसा कर सकता था और साबित कर सकता था उसने अपने भाई अपीलकर्ता, ए के खिलाफ आरोप लगाए थे और इस प्रकार इस प्रक्रिया में गलत तरीके से बोझ डाल दिया गया प्रमाण का. [पैरा 22, 26 और 27(1)] [385-डी; 386-जी-एच; 387-सी]

थिरुवेंगडा पिल्लई बनाम नवनीतम्मल एवं अन्य, 2008 (3) एससीआर 23 = एआईआर 2008 एससी 1541; के. लक्ष्मणन बनाम थेक्कयी/बी पद्मिनी एवं अन्य, 2008 (16) एससीआर 1117 =एआईआर 2009 एससी 951; एवं कृष्ण मोहन कु/@नानी चरण कु/ एवं अन्य। वी प्रतिमा मैती एवं अन्य। 2003 सप्ल. (3) एससीआर 496 = एआईआर 2003 एससी 4351 - संदर्भित।

2.4. दस्तावेज़ पूर्व. 83 दिनांक 29 जुलाई 1983 सी है दस्तावेज़ उदा.ए-6 के आगे, जिसमें निपटानकर्ता ने लिखा था प्रतिवादी नंबर 1 कि उसने उसे दरवाजा नंबर 23 दिया था। इस प्रकार, बंदोबस्तकर्ता का कभी भी अन्यथा इरादा नहीं था। [पैरा 27(vi)] [388-सी]

केस कानून संदर्भ: 2010 (8) एससीआर 299 पैरा 6 पर निर्भर था

2007 (8) एससीआर 697 पैरा 6 पर निर्भर था

1951 एससीआर 548 पर भरोसा किया गया इ पैरा 8

एआईआर 1920 पीसी 65 को पैरा 9 में संदर्भित किया गया है

1964 एससीआर 270 पैरा 10 पर निर्भर था 1967 एससीआर 331 पैरा 11 एफ पर निर्भर

1976 (2) एससीआर 327 पैरा 12 पर निर्भर था

1999 (2) सप्ल. एससीआर 216 पैरा 13 को संदर्भित करता है

एआईआर 1983 एससी 684 पैरा 14 जी पर निर्भर था

2010 (10) एससीआर 30 पैरा 15 पर निर्भर था

2011 (5) एससीआर 587 पैरा 15 पर निर्भर था जेटी

2013(2) एससी 362 पैरा 15 पर निर्भर था

2008 (3) एससीआर 23 का उल्लेख किया गया है पैरा 16

2008 (16) एससीआर 1117 का उल्लेख किया गया है पैरा 17

2003 (3) पूरक। एससीआर 496 का उल्लेख किया गया है पैरा 18

सिविल एपी पेला ते क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या। सी 2004 का 2178-2179. के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.07.2003 से ए.एस. में

मद्रास में उच्च न्यायालय 1987 की संख्या 1104 और स्थानांतरित ए.एस. 2001 की संख्या 1120. साथ

सीए। 2004 की संख्या 2184-2185।

आर. बालासुब्रमण्यम, एस. नंदा कुमार, आर. सतीश कुमार, 0 परिवेश सिंह अंजलि चौहान, करुणाकरण, एस.के. बंधोपाध्याय, राकेश के. शर्मा, वी.एन. रघुपति के लिए अपीलकर्ता.श्याम नंदन, नेहा अग्रवाल, करुण मेहता, डब्लू अमन, उत्तरदाताओं के लिए वरुण टंडन, सुब्रमण्यम प्रसाद।

न्यायालय ने अभिनिर्धरति सुनाया गया

डॉ० बी.एस. चौहान, जे. 1. ये अपीलें की गई हैं आक्षेपित निर्णय और दिनांकित डिक्री के विरूद्ध पसंदीदा १६.७.२००३ को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ए०एस० में पारित किया गया। नहीं। १९८७ का एफ ११०४ आैर स्थानांतरित ए०एस० २००१ की संख्या ११२०, जिसमें इसने ट्रायल कोर्ट के फैसले आैर डिक्री को रदद कर दिया है अपीलकर्ता के मुकदमें पर फैसला सुनाया था आैर मुकदमे को खारिज कर दिया था आैर मुकदमे को खारिज की दिया था। प्रतिवादी नंबर १ जी२ इन्हें जन्म देने वाले तथ्य एवं परिस्थितियाँ अपीलें हैं

ए. चुनाव लडने वाली पाटिर्यां किसके बेटे आैर बेटी हैं। स्व० बी०पी० रेतीला। हालाँकि दिवंगत बी०पी० सैंडी के कई बच्चे थे, एच ने अपनी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए, अपने दोनों को स्थानांतरित/सेटल करने का निर्णय लिया। मकान संख्या 22 और 23,

पेरिया पल्ली स्ट्रीट, राजा ए अन्नामलाई पुरम, चेन्नई-28 अपने सबसे छोटे बेटे के पक्ष में और बेटी (यहाँ चुनाव लड़ रही पार्टियाँ) क्रमशः। इसलिए, पार्टियों के पिता ने दो पंजीकृत निष्पादित किए 27.8.1981 को निपटान विलेख संख्या अंकित। 1690/81 और 1691/81 उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय, मायलापुर, चेन्नई, मकान नंबर 23 को अपनी बेटी के नाम पर स्थानांतरित करना (प्रतिवादी नंबर 1) और मकान नंबर 22 उसके बेटे के नाम पर (अपीलकर्ता).

बी. अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पार्टियों के पिता बाद में ही एहसास हुआ कि मकान नंबर 23 जो बेटी को दिया गया, उसे देना चाहिए था उसे और बेटी को मकान नंबर 22. इस प्रकार, पार्टियों को देने के लिए उनके पिता के वास्तविक इरादे के प्रभाव ने आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया उन्हें दी गई संपत्तियाँ, और उसके आगे, पर समान विनिमय करने के लिए एक समझौता विलेख निष्पादित किया 1.6.1982. उक्त दस्तावेज़ शीला डॉस द्वारा देखा गया था और श्रीमती मैरी डॉस, जो पड़ोसी और शिक्षक थीं बेटी के सहकर्मी - प्रतिवादी नंबर 1. चूँकि, कहा गया है समझौता दिनांक 1.6.1982 (उदा.ए-3) को प्रभावी नहीं किया गया था प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा, अपीलकर्ता ने O.S.No दायर किया। ई का 6331 1983 दिनांक 12.9.1983 को सिटी सिविल जज, चेन्नई की अदालत में, प्रतिवादी/प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश जारी करने के लिए सुधार विलेख निष्पादित करें और आगे से उसे रोकें वाद की संपत्ति पर अपीलकर्ता के

कब्जे में हस्तक्षेप। इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, श्री बी.पी. सैंडी और एफ अपीलकर्ता ने 8.10.1983 को एक सुधार विलेख (Ex.A-6) निष्पादित किया जिसके द्वारा डोर नंबर 23 में संपत्ति अपीलकर्ता को दी गई थी। उक्त विलेख पर दो गवाहों सुसान मुथु और द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ए बर्नार्ड। प्रतिवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी ने मुकदमा ओ.एस. दायर किया। नहीं। 1984 का 415 उसी न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करने के लिए कि जी समझौता दिनांक 1.6.1982 (उदा.ए-3), एक अपंजीकृत दस्तावेज़, एक जाली दस्तावेज़ होने के कारण शून्य और शून्य था, और वह उसने अनुचित प्रभाव में आकर रिक्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर.

सी. ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुकदमों का फैसला एक साथ किया निर्णय और डिक्री दिनांक 21.8.1986 जिसके माध्यम से अपीलकर्ता के मुकदमे का फैसला सुनाया गया और प्रतिवादी नंबर 1 का फैसला सुनाया गया बर्खास्त.

डी. व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले अपील दायर की विद्वान जिला न्यायाधीश, तथापि, यह बाद में था हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है दोनों अपीलें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गईं।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस दौरान अपीलों के लंबित रहने पर, अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट मिला डिक्री को न्यायालय के

माध्यम से निष्पादित किया गया और बाद में बेच दिया गया प्रतिवादी क्रमांक 2 को संपत्ति क्रमांक 23 इसलिए, ये अपीलें.

3. श्री आर. बालासुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होकर, उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया है कि वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में त्रुटि हुई है कानून का और यह आवश्यक नहीं था, कि बीच में समझौता हो पार्टियां, बेचने के समझौते के समान, हो सकती हैं की धारा 17 के तहत आवश्यक ई पंजीकृत दस्तावेज़ पंजीकरण अधिनियम या संपत्ति के हस्तांतरण के किसी भी प्रावधान द्वारा अधिनियम और, इसलिए, उच्च न्यायालय ने एक्सटेंशन.ए को रोककर गलती की कानून में अस्वीकार्य और निष्क्रिय था। एक बार दस्तावेज़ (उदा.ए-3) को बिना किसी साक्ष्य के स्वीकार कर लिया गया था यदि आपत्ति उठाई गई तो इसकी विषयवस्तु को स्वीकार किया जाना अनिवार्य था और भरोसा किया. वास्तव में, उक्त दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था पार्टियों द्वारा अपने वास्तविक इरादे को कार्यान्वित करने के लिए पिता। अत: अनुचित प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता अनुमान लगाया गया. ट्रायल कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए जी को अपीलीय अदालत ने पलट दिया। पार्टियां संयुक्त रूप से ऋण लिया, पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ अपीलकर्ता द्वारा संपूर्ण ऋण का भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है प्रतिवादी संख्या 1 के विवाह और भरण-पोषण के लिए लिया गया, वह उस संपत्ति

को अपने नाम पर हस्तांतरित कर देगी। इस प्रकार एच अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

4. श्री श्याम डी. नंदन, ए पर उपस्थित विद्वान वकील प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से, उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया है ने ट्रायल कोर्ट के निर्णयों और डिक्री को सही ढंग से उलट दिया है वैधानिक प्रावधानों की सही व्याख्या करना और उन्हें लागू करना परिप्रेक्ष्य। यह अनुचित प्रभाव का स्पष्ट मामला था। सुधार विलेख (उदा.ए-6) पिता और द्वारा निष्पादित अपीलकर्ता को इस पर प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए था।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या १ के रूप में कोई पार्टी नहीं थी दस्तावेज़ एक्सटेंशन.ए 6 के अनुसार, वह इससे बंधी नहीं थी। यह भी अपीलकर्ता निपटान में सुधार के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सका विलेख- उदाहरण ए-1, क्योंकि सी को समझने में कोई गलती नहीं हुई थी या पार्टियों द्वारा निष्पादन. दोनों पार्टियों के जनक नहीं थे ट्रायल कोर्ट के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उससे पूछताछ की गई, हालांकि वह था मुकदमा संस्थित होने के समय भी जीवित है। यहां तक कि अपीलकर्ता भी दस्तावेज़एक्सटेंशन.ए -3 के गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा। वह केवल श्री ए. बर्नार्ड, दस्तावेज़ के गवाह एक्सटेंशन.ए .A-D.) से पूछताछ की गई 6), जिसका तत्काल मामले से कोई लेना-देना नहीं था .. इस प्रकार, अपीलें योग्यता की कमी है और बर्खास्तगी के योग्य हैं।

5. हमने द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है उभय पक्षों के विद्वान वकील ने अभिलेखों का अवलोकन किया। ई से पहले मामले के गुण-दोषों में प्रवेश करते हुए, इसकी जांच करना वांछनीय है कानूनी मुद्दों।कानूनी मुद्दों:।. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 26। 1963:विशेष राहत अधिनियम 1963 की धारा 26 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में जाना जाता है) उपकरणों के सुधार के लिए प्रदान करता है, जहां धोखाधड़ी या पार्टियों की आपसी गलती के माध्यम से, ए लिखित रूप में साधन वास्तविक अभिप्राय को व्यक्त नहीं करता है, तो जी पार्टियां सुधार के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालाँकि, खंड 4 उसमें प्रावधान है कि ऐसी राहत नहीं दी जा सकती अदालत, जब तक कि इसका विशेष रूप से दावा न किया गया हो।

6. सुभद्रा एवं अन्य में। वी. थैंकम, एआईआर 2010 एससी 3031, यह न्यायालय इस पर निर्णय लेते समय कि क्या समझौता प्रभावित होता है किसी भी अस्पष्टता से और क्या सुधार की आवश्यकता है, आयोजित किया गया कि जब पूरी संपत्ति का विवरण दिया गया है और मामले अस्पष्टता से परे होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में सुधार का प्रश्न, इस प्रकार, उत्पन्न नहीं होता. अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान होंगे 8 सीमित मामलों में आकर्षित होंगे। इस धारा के प्रावधान ऐसा करते हैं सामान्य अनुप्रयोग नहीं है. ये हो सकते हैं प्रावधान केवल उन्हीं मामलों में आकर्षित होता है जहां सामग्री बताई गई है अनुभाग संतुष्ट

हैं. सुधार की राहत का दावा किया जा सकता है जहां यह धोखाधड़ी या आपसी गलती से हुआ हो सी पार्टियाँ कि पार्टियों का वास्तविक इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है एक उपकरण के संबंध में. डी राज्य में इस न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण दोहराया गया हैकामताका और अन्य की। बनाम के.के. मोहनदास और आदि, एआईआर 2007 एससी 2917.

7. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि धारा अधिनियम के 26 का अनुप्रयोग सीमित है और यह केवल लागू होता है जहां यह दलील दी जाती है और साबित किया जाता है कि धोखाधड़ी या पारस्परिक माध्यम से पार्टियों की गलती, पार्टियों की असली मंशा नहीं ई एक उपकरण के संबंध में व्यक्त किया गया। ऐसा सुधार है केवल लिखत के पक्षकारों द्वारा ही स्वीकार्य है, किसी के द्वारा भी नहीं अन्यथा। एफ जी एच द्वितीय. अनुचित प्रभाव • संविदा अधिनियम की धारा 16। 1872:अनुबंध अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि एक अनुबंध है कहा जाता है कि यह संबंध "अनुचित प्रभाव· से प्रेरित है पार्टियों के बीच अस्तित्व इस प्रकार है कि पार्टियों में से एक दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है, और उसका उपयोग करता है दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति।

8. बिशुनदेव नारायण और अन्य में। वी. सेओगेनी राय और जगेमठ, एआईआर 1951 एससी 280, इस मुद्दे से निपटते समय, यह न्यायालय ने कहा:

> "...धोखाधड़ी, 'अनुचित प्रभाव' और जबरदस्ती के मामलों में, इसका अनुरोध करने वाले पक्षों को पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा और मामले का निर्णय केवल दिए गए विवरण के आधार पर ही किया जा सकता है। वहां साक्ष्य में उनसे कोई विचलन नहीं हो सकता। सामान्य आरोप महज एक बयान के बराबर भी अपर्याप्त हैं हालाँकि किसी भी अदालत को धोखाधड़ी का नोटिस लेना चाहिए जिस भाषा में उन्हें समझाया जाता है वह मजबूत हो सकती है, और यही बात अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती पर भी लागू होती है।"

9. पूसथुराई बनाम कन्नप्पा चेट्टियार में प्रिवी काउंसिल, एआईआर 1920 पीसी 65 ने तर्क दिया कि अनुचित व्यवहार करना एक गलती है संबंधों के प्रमाण द्वारा स्थापित किया गया प्रभाव पार्टियों की स्थिति ऐसी रही है कि कोई स्वाभाविक रूप से सी पर भरोसा करता है सलाह के लिए दूसरे पर निर्भर था और दूसरा ऐसा करने की स्थिति में था इसे देने में पहले की इच्छा पर हावी होना। उस बिंदु तक अकेले "प्रभाव" को ही बाहर कर दिया गया है। ऐसा प्रभाव हो सकता है बुद्धिमानी से, विवेकपूर्ण ढंग से और मददगार ढंग से उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या कानून के

अनुसार भारत या इंग्लैण्ड का कानून, केवल प्रभाव से अधिक होना चाहिए कानून की भाषा में प्रभाव डालने के लिए ऐसा साबित किया गया, डी 'अनुचित'.

10. लाडली प्रसाद जयसवाल बनाम द कमल डिस्टिलरी कंपनी में। लिमिटेड, कमल एवं अन्य, एआईआर 1963 एससी 1279, इस न्यायालय ने कहा:

> "सामान्य कानून के तहत 'अनुचित प्रभाव' का सिद्धांत अनुदान के लिए इंग्लैंड में न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था अभ्यास द्वारा प्राप्त लेनदेन के विरुद्ध सुरक्षा आध्यात्मिक और लौकिक प्रभाव के घातक रूप। सिद्धांत इनाम के कृत्यों के साथ-साथ अन्य एफ पर भी लागू होता है लेन-देन जिसमें एक पक्ष अपने पद का प्रयोग करके प्रभुत्व से दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त होता है। भारतीय अधिनियम काफी हद तक नियमों पर आधारित है अंग्रेजी आम कानून का. S.16 का पहला उप-भाग बताता है सामान्य शब्दों में सिद्धांत को नीचे रखें। उपधारा (2) द्वारा एक जी धारणा उत्पन्न होती है कि एक व्यक्ति को समझा जाएगा यदि परिस्थितियाँ हों तो दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में उसमें निर्धारित पूरा हो गए हैं. उपधारा (3) बताती है खंडनयोग्य अनुमान लगाने के लिए शर्तें कि

a लेनदेन अनुचित प्रभाव के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। तीसरे उपधारा में नियम का कारण यह है कि वह व्यक्ति जिसने दूसरे पर लाभ प्राप्त किया हो अपनी इच्छा पर हावी होने की स्थिति में भी रह सकता है की दलील के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य को दबा दें अवांछित प्रभाव।"

11. सुभाष चंद्र दास मुशीब बनाम गंगा प्रसाद में दास मुशीब और अन्य, एआईआर 1967 एससी 878, इस न्यायालय ने माना कि अनुचित प्रभाव के मामले की सुनवाई कर रही अदालत को दो पर विचार करना चाहिए आरंभ करने वाली चीजें, अर्थात्, (1) के बीच संबंध हैं दाता और प्राप्तकर्ता, इस प्रकार कि प्राप्तकर्ता सक्षम हो सी दाता की वसीयत पर हावी है, और (2) प्राप्तकर्ता ने उसका उपयोग किया है दाता पर अनुचित लाभ प्राप्त करने की स्थिति? ऊपर इन दोनों मुद्दों के समाधान के बाद एक तीसरा बिंदु सामने आता है, जो कि जांच का दायित्व है। यदि लेनदेन प्रकट होता है बेहूदा होना, तो साबित करने का बोझ कि अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं किया गया था डी व्यक्ति जो दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है। यह आगे कहा गया कि केवल इसलिए कि पार्टियाँ लगभग थीं एक-दूसरे से संबंधित या केवल इसलिए कि दाता बूढा था या कमजोर चरित्र का कोई भी व्यक्ति अनुचित प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता उठना। आम तौर पर वकील और मुवक्किल के संबंधों की बात करें तो, ई ट्रस्टी और सेस्टुई क्यू ट्रस्ट, आध्यात्मिक सलाहकार और भक्त,

इसमें चिकित्सा परिचारक और रोगी, माता-पिता और बच्चे शामिल हैं जिससे ऐसी धारणा उत्पन्न होती है।

12. अफसर शेख और अन्य बनाम सोलेमन बीबी और अन्य में, एआईआर एफ 1976 एससी 163, इस न्यायालय ने कहा:

> "उपहार अंतर के मामले में अनुचित प्रभाव के बारे में कानून विवोस एक अनुबंध के मामले के समान ही है। उपधारा धारा 16 के (3) में साक्ष्य का नियम शामिल है। अनुसार इस नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लेन-देन से बचना चाहता है अनुचित प्रभाव का आधार सिद्ध होता है-
>
> (ए) कि जिस पार्टी ने लाभ प्राप्त किया था, वह थी भौतिक समय, दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में लाभ प्रदान करना, और

(बी) कि लेनदेन अनैतिक है, ए लेन-देन से लाभ प्राप्त करने वाली पार्टी पर बोझ बदल जाता है यह दिखाने के लिए कि यह अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं था। या तो इन दोनों स्थितियों में से कोई भी बोझ स्थापित नहीं होगा शिफ्ट नहीं. जैसा कि वर्तमान में चर्चा की जाएगी, तत्काल 8 में यदि पहली शर्त स्थापित नहीं की गई थी; और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पर कभी भी बोझ नहीं पड़ा। रघुनाथ प्रसाद बनाम सरजू प्रसाद में प्रिवी काउंसिल, (एआईआर 1924 पीसी 60) ने इसके लिए तीन चरणों की व्याख्या की अनुचित प्रभाव के मामले पर विचार. यह इंगित किया गया

था ' पहली बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या सी वादी या पक्ष जो अनुचित आधार पर राहत चाहता है प्रभाव ने साबित कर दिया है कि पार्टियों के बीच संबंध एक-दूसरे से ऐसे संबंध हैं कि कोई भी हावी होने की स्थिति में है दूसरे की इच्छा. इस बिंदु तक, केवल 'प्रभाव' ही पड़ा है बाहर किया गया. एक बार वह स्थिति प्रमाणित हो जाने पर, डी दूसरे चरण पर पहुँच गया है - अर्थात्, मुद्दा क्या लेनदेन अनुचित तरीके से प्रेरित किया गया है प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है पार्टियों के संबंधों को दिखाने के लिए राहत की मांग की जा रही है ऐसे रहे हैं कि एक स्वाभाविक रूप से दूसरे ई पर निर्भर रहा सलाह के लिए, और दूसरा हावी होने की स्थिति में था इसे देने में प्रथम की इच्छा. के निश्चय पर मुद्दे के दूसरे चरण में एक तीसरा बिंदु सामने आता है, जो जांच का दायित्व है। यदि लेनदेन प्रतीत होता है बेहूदा, तो यह साबित करने का बोझ कि यह एफ नहीं था अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर उस व्यक्ति पर झूठ बोलना है दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में था। त्रुटि है यदि इन प्रस्तावों का क्रम हो तो इसका उत्पन्न होना लगभग निश्चित है बदला हुआ। सौदेबाजी की अनैतिकता नहीं है विचार करने योग्य पहली बात. सबसे पहले मानी जाने वाली बात जी पार्टियों का रिश्ता है. क्या वे ऐसे थे जो एक डालते दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में" (महत्व जोड़ें)

13. यदि अनुमान को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर तथ्य मौजूद हैं अनुचित प्रभाव का, अनुचित का आरोप लगाने का लोप विशेष रूप से प्रभाव, वादी के हकदार होने के लिए घातक नहीं है उस ज़मीन पर राहत के लिए; न्यायालय को बस यही देखना है प्रतिवादी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है. हरि सिंह बनाम कन्हैया लाल में, एआईआर 1999 एससी 3325, यह माना गया कि इसमें केवल विवरण का अभाव है बी दलीलें इस कारण से किसी मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकतीं इसे पक्षों द्वारा साक्ष्य के माध्यम से पूरक किया जा सकता है।

बीमार. दस्तावेज़ की स्वीकार्यता:

14. बिहार राज्य एवं अन्य में। वी. राधा कृष्ण सिंह और सी.ओ.आर.एस., एआईआर 1983 एससी 684, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> "किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता एक बात है और यह संभावित है मूल्य बिल्कुल अलग ये दो पहलू नहीं हो सकते संयुक्त. एक दस्तावेज़ स्वीकार्य हो सकता है और फिर भी हो सकता है इसके संभावित मूल्य का कोई दृढ़ विश्वास और महत्व नहीं है शून्य हो सकता है...जहां एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, जो है गवाहों और दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर और है "इसमें एक वैधानिक स्वाद है कि यह केवल किसी के द्वारा नहीं दिया

जाता है प्रशासनिक अधिकारी लेकिन एक क़ानून के अधिकार के तहत, इसका संभावित मूल्य वास्तव में बहुत अधिक होगा बड़े वजन का हकदार.दस्तावेज़ों का संभावित मूल्य, चाहे कितना भी प्राचीन क्यों न हो हो सकता है, वे अपनी जानकारी के स्रोतों का खुलासा न करें या पर्याप्त बदनामी हासिल नहीं की है, यह बहुत कम है।"

15. मदन मोहन में उपरोक्त प्रस्ताव को दोहराते हुए सिंह एवं अन्य बनाम रजनी कांत एवं अन्य, एआईआर 2010 एससी 2933, यह न्यायालय ने माना कि एक दस्तावेज़ स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जी क्या उसमें निहित प्रविष्टि का कोई संभावित मूल्य हो सकता है अभी भी तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी आवश्यक है किसी विशेष मामले का. (यह भी देखें: एच.सिद्दीकी (मृत) एलआरएस द्वारा। वी. ए.रामलिंगम एआईआर 2011 एससी 1492; लक्ष्मीबाई (मृत) तृ. Lrs. और अन्य बनाम भगवंतबुवा (मृत) thr Lrs। एवं अन्य, जेटी 2013(2) एससी एच 362)?चतुर्थ. सबूत का दायित्व:

16. थिरुवेंगडा पिल्लई बनाम नवनीतम्मल और अन्य में, AIR 2008 SC 1541, इस न्यायालय ने माना कि जब का निष्पादन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत एक अपंजीकृत दस्तावेज़ को अस्वीकार कर दिया गया प्रतिवादियों द्वारा, यह निर्णय कि यह स्थापित करना प्रतिवादियों का काम है कि दस्तावेज़ जाली या मनगढ़ंत था, यह नहीं है ध्वनि प्रस्ताव. प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने इस पर कार्यवाही की आधार यह है कि यह उस पार्टी पर निर्भर करता है जो दावा करता है कि उसे कुछ साबित करना है चीज़; और जैसा कि प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि समझौता था जाली, इसे साबित करना उनका काम था। लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय इस तथ्य से ध्यान भटक गया कि दस्तावेज़ को प्रतिपादित करने वाला पक्ष सी इसे साबित करना होगा. यह वादी ही था जो न्यायालय आया था यह आरोप लगाते हुए कि पहले प्रतिवादी ने एक समझौता निष्पादित किया था उसके पक्ष में बिक्री. प्रतिवादी ने इससे इनकार किया, यह बोझ है वादी को यह साबित करना था कि प्रतिवादी ने हत्या की है समझौता और प्रतिवादी पर नकारात्मक साबित करने के लिए नहीं।

17. के. लक्ष्मणन बनाम थेक्कयिल पद्मिनी और अन्य में, एआईआर 2009 एससी 951, इस न्यायालय ने माना कि जब कोई संदिग्ध हो वसीयत के निष्पादन के संबंध में परिस्थितियाँ, उत्तरदायित्व है उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाने के लिए प्रस्तावक पर भी न्यायालय और केवल जब ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, ई कोर्ट वसीयत को असली मानेगा। यहां तक कि जहां हैं भी ऐसी कोई दलील नहीं है, लेकिन हालात संदेह पैदा करते हैं, यह जारी है न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए प्रस्तावक। ऐसे अनेक कारणों से संदिग्ध परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता के संबंध में, एफ वसीयतकर्ता के मन की स्थितियाँ, उसमें बने स्वभाव वसीयत का अप्राकृतिक, असंभाव्य या

अनुचित होना या हो सकता है वसीयत में अन्य संकेत यह दर्शाते हैं कि वसीयतकर्ता का मन क्या था मुक्त नहीं। ऐसे मामले में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से यही अपेक्षा करेगा जी के सामने सभी वैध संदेह पूरी तरह से दूर हो जाने चाहिए दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

18. कृष्ण मोहन कु/@नानी चरण कु/ एवं अन्य में। वी प्रतिमा मैती एवं अन्य, एआईआर 2003 एससी 4351, यह माना गया कि जब एच द्वारा धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या अनुचित प्रभाव का आरोप लगाया गया है किसी मुकदमे में आम तौर पर ऐसा साबित करने का भार पक्षकार पर होता है धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी। लेकिन, जब व्यक्ति दूसरे और दूसरे के साथ प्रत्ययी रिश्ते में है को साबित करने का भार सक्रिय रूप से आत्मविश्वास की स्थिति में है धोखाधड़ी, गलतबयानी या अनुचित प्रभाव का अभाव है बी जो व्यक्ति प्रभुत्व की स्थिति में है, उसे वहां यह साबित करना होगा लेन-देन में निष्पक्ष खेल था और यह कि स्पष्ट ही वास्तविक है, दूसरे शब्दों में कहें तो लेन-देन वास्तविक और प्रामाणिक है। में ऐसे मामले में नेकनीयती साबित करने का बोझ लेन-देन का भार प्रमुख पक्ष पर डाल दिया जाता है, अर्थात्, C वह पार्टी जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।

19. तत्काल मामले का प्रकाश में अभ्यास करना आवश्यक है कानून के उपरोक्त तयशुदा प्रस्ताव के.

20. इसमें कोई विवाद नहीं है कि निपटान विलेख दिनांक द्वारा 27.8.1981, स्वर्गीय श्री बी.पी. सैंडी ने मकान नंबर 23 बताया था डी का माप 2413 वर्ग है। फ़ुट. बेटी को - प्रतिवादी क्रमांक 1 और मकान नंबर 22 जिसका माप 730 वर्ग है। फ़ुट. बेटे को - अपीलकर्ता इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने वाला कोई भी गवाह नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा जांच की गई थी चाहे स्वर्गीय बी.पी. पार्टियों के पिता सैंडी ने व्यक्त किया था उनके समक्ष संपत्तियों के संबंध में कोई इरादा. उदा.ए-6 दिनांक 28.10.1983 के बाद एक अपंजीकृत दस्तावेज़ है Exs.A 1 और A2, जिसके द्वारा पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी मकान नंबर 23 अपीलार्थी पुत्र को दिया जाए। अपीलकर्ता ने साक्ष्यांकित गवाहों में से एक की जांच की है। एफ बर्नार्ड लेकिन उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 दस्तावेज़ का पक्षकार नहीं था, वह है मामले पर क़ानूनी तौर पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं। अत: ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में यह देखना होगा कि इसका असर क्या होता है दस्तावेज़ दिनांक 1.6.1982 Ex.A-3, का ज्ञापन जी समझौता, और क्या यह इसके द्वारा प्राप्त किया गया था अपीलकर्ता पर अनुचित प्रभाव डाला गया। दस्तावेज़ में ऐसा कहा गया है उनके पिता द्वारा किये गये समझौता विलेख में गलतियाँ होना मई 1982 के अंतिम सप्ताह में ही पार्टियों का पता चला, उन्होंने त्रुटि को सुधारने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने एच इसे सुधारने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित और पंजीकृत करेगा

गलती। इस तरह के सुधार के पीछे का उद्देश्य, ए बनाना है अपीलकर्ता मकान नंबर 23 का हकदार है और प्रतिवादी नंबर 1 ·" मकान नंबर 22.

21. ट्रायल कोर्ट के समक्ष, केवल पक्षकार और श्री ए. बर्नार्ड, विलेख (उदा.ए-6) के प्रमाणित गवाह थे जांच की गई. अपीलकर्ता ने अपने पिता से भी पूछताछ नहीं की जो बी 26.12.1983 तक जीवित थे। अपीलकर्ता सहारा ले सकता था नागरिक संहिता के आदेश XVIII नियम 16 के तहत प्रावधानों के लिए प्रक्रिया, 1908, इस गवाह की तुरंत जांच करने के लिए। श्री ए की परीक्षा बर्नार्ड, (पीडब्लू-2) वास्तविकता के बारे में Ex.A-6 का एक निरर्थक व्यायाम था, क्योंकि उक्त दस्तावेज़ C नहीं हो सका मामले के फैसले पर कोई असर पड़ेगा.

22. ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया था कि, भले ही अपीलकर्ता ने Ex.A-3 के प्रमाणित गवाह की जांच नहीं की प्रतिवादी ऐसा कर सकती थी और अपने आरोपों को साबित कर सकती थी उसके भाई अपीलकर्ता के खिलाफ बनाया गया, और इस प्रकार इस प्रक्रिया में सबूत का बोझ गलत तरीके से स्थानांतरित कर दिया था। न्यायालय ने आगे कहा यह अपीलकर्ता ही था जो Ex.A-3 प्राप्त करना चाहता था निष्पादित किया गया, इस प्रकार, साबित करने का दायित्व उस पर था, यदि वह मुक्त हो जाता वही, तभी इसे प्रतिवादी नंबर 1/ पर स्थानांतरित किया जा सकता है प्रतिवादी.

23. अदालत ने आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादी एक था महिला पढ़ी-लिखी है और शिक्षिका के पद पर कार्यरत है, ऐसा उसका आरोप है कोरे

गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुचित प्रभाव डालना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि उदा.ए -3 F था उसके द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित एक दस्तावेज़ और, इसलिए, यह उसके लिए बाध्यकारी था और यह उसके लिए स्वीकार्य नहीं था यह कहना कि यह एक जाली दस्तावेज़ था।

विद्वान निचली अदालत ने दिनांकित एक पत्र पर भी ध्यान दिया था 19.7.1983 (उदा.बी-3) पार्टियों के पिता द्वारा जी को लिखा गया _प्रतिवादी संख्या 1 जिसमें यह कहा गया था कि उसने उसे दिया था मकान नंबर 23. हालाँकि, उक्त पत्र को यूं ही रफा-दफा कर दिया गया बिना कोई कारण बताए न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।

24. उपरोक्त मुद्दों से निपटते समय उच्च न्यायालय, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उदा.ए -6 पूरी तरह से असंगत था प्राकृतिक मानव आचरण और यदि बसने वाला अर्थात पिता पार्टियों का इरादा गलती को सुधारने का था, तो वह ऐसा कर सकते थे सुधार विलेख को बहुत अच्छी तरह से पंजीकृत किया गया। अदालत ने आगे कहा कि एक बार ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उदा.ए-6 था स्वीकृति के लायक नहीं, इसे देना जायज़ नहीं था बी विलेख के सुधार की एक न्यायसंगत राहत। ए पर भरोसा करने के बाद इस न्यायालय के निर्णयों की बड़ी संख्या, उच्च न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अनुचित प्रभाव का मामला था और कथित

दस्तावेज़ उदा.ए को निष्पादित करने की तिथि के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित थी और उस पर निर्भर थी सी पिता और भाई ने उसकी शादी तय करने और भरण-पोषण के लिए, क्योंकि उनकी शादी 1.6.1983 को ही संपन्न हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि वादी एक में था उसकी वसीयत पर हावी होने की स्थिति, इस प्रकार, दस्तावेज़उदा.ए-3 थी अविवेकपूर्ण कहा गया है। यह एक ऐसा मामला था, जिसमें, उसके बाद 0 हस्ताक्षर प्राप्त करना 4 प्रतिवादी सं. कुछ पर 1 कागजात, दस्तावेज़ को लिखा गया था। के प्रति सम्मान के साथ दस्तावेज़, उच्च न्यायालय ने माना कि उक्त दस्तावेज़उदा.ए-3 एक टाइप किया हुआ दस्तावेज़ होने के नाते, इसमें का नाम शामिल होना चाहिए वह व्यक्ति जिसने इसे लिखा था। इसने आगे तर्क दिया कि उसमें प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि इसे किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया था फ़ील्ड में और इस प्रकार, संपूर्ण दस्तावेज़ धूमिल हो गया है संदेह और अस्पष्टीकृत परिस्थितियाँ।

25. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उदा.ए-3 एक है अपंजीकृत दस्तावेज़, पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और एफ इसे गलत तरीके से स्वीकार किया गया था। हमारी राय में ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है कानूनी तौर पर सही नहीं होगा. हालाँकि, उक्त निष्कर्ष को उलट दिया गया है अपीलकर्ता के पक्ष में संतुलन नहीं झुकाएगा।

26. यहां ऊपर उल्लिखित नियम के अनुसार, यह क्रिस्टल है स्पष्ट है कि दस्तावेज़ भले ही स्वीकार्य हो, फिर भी जी इसकी सामग्री को साबित

करना होगा और तत्काल मामले में, जैसा कि अपीलकर्ता ने प्रमाणित करने वाले किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की दस्तावेज़, न ही इसकी सामग्री साबित हुई, इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता हमारे सामने आक्षेपित निर्णय। अधिनियम की धारा 26, यदि पार्टियों को ऐसा लगता है तो दस्तावेज़ में सुधार का प्रावधान है एच उनसे कोई गलती हुई है. इसके अलावा, ii केवल, पिता था उन पक्षों की जो विलेख में सुधार की मांग कर सकते थे। ए यहां पार्टियों द्वारा मात्र सुधार से मामला शांत नहीं होता अधिनियम की धारा 26 के दायरे में। संज्ञान लेते हुए अनुबंध अधिनियम की धारा 16 के वैधानिक प्रावधान और सिद्धांत के आवेदन के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरामीटर अनुचित प्रभाव पर उच्च न्यायालय सही बी पर पहुंच गया है निष्कर्ष।

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित पर पहुँचे अपरिहार्य निष्कर्ष:

(i) किसी भी पक्ष ने साक्ष्यांकित गवाह सी की जांच नहीं की है दस्तावेज़ उदा.ए 3 के लिए। ऐसे तो एक गवाह ही समझा सकता था पार्टियों का आचरण और गवाही दी गई कि किसने तैयारी की थी दस्तावेज़ उदा.ए 3.

(ii) विलेख की भाषा (उदा.ए-3) से यह स्पष्ट है कि इसे किसी वकील या डीड राइटर द्वारा तैयार किया गया है।

(iii) उक्त दस्तावेज़ (उदा.ए-3) में ये दोनों शामिल नहीं हैं हस्ताक्षर, या लेखक का पता. अपीलकर्ता के पास भी है न तो मुंशी से पूछताछ की और न ही यह बताया कि ऐसा व्यक्ति कौन है था। इससे सम्मान को लेकर सही स्थिति का पता चलता क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने कोरे कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, या ई क्या वह दस्तावेज़ के निष्पादन के लिए उसके पास आई थी प्रमाणित गवाहों और अपीलकर्ता के साथ। इसके अतिरिक्त, मुंशी बता सकते थे कि नॉन ज्यूडिशियल किसने खरीदा था दस्तावेज़ के लिए स्टाम्प पेपर। ए-3.\

(iv) दस्तावेज़ निष्पादित करने पर विचार उदा.ए-3) संयुक्त रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति का मोचन प्रतीत होता है दोनों पक्षों द्वारा, एक अधिवक्ता कृष्णास्वामी को, जिनके साथ एफ शीर्षकउदा.ए 1 और Ex.A2 के कार्यों को सुरक्षा के रूप में रखा गया था। अपीलकर्ता द्वारा उक्त गिरवीदार की जांच नहीं की गई है यह दिखाने के लिए कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 भी जी का पक्षकार था बंधक और जिसने उसकी संपत्ति का स्वामित्व विलेख रखा था उनके साथ।

(v) अपने मुख्य परीक्षण में, अपीलकर्ता ने एक बनाया था झूठा बयान कि उसे समझौते के बारे में अवगत नहीं कराया गया 26 जून 1982 तक विलेख उदा.ए-1, जैसा कि उन्हें दिया गया था उसकी माँ अपनी मृत्यु से पहले उस तारीख को। ऐसा बयान दस्तावेज़उदा.ए-1 से पता चलता है कि यह पूरी तरह से गलत है, कि उस पर उसके पिता ने कब्ज़ा कर लिया

था प्रतिवादी संख्या 1 की अनुमति, द्वार संख्या 23 में संपत्ति के रूप में बी उसे दे दिया गया था और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 को उक्त का आनंद लेने का पूर्ण अधिकार था संपत्ति।

(vi) दस्तावेज़ पूर्व. 83 दिनांक 29 जुलाई 1983 बाद का है दस्तावेज़ उदा.ए-6 के लिए, जिसमें निपटानकर्ता श्री सैंडी ने लिखा था सी प्रतिवादी नंबर 1 कि उसने उसे दरवाजा नंबर 23 दिया था। इस प्रकार, बंदोबस्तकर्ता का कभी भी अन्यथा इरादा नहीं था।

(vii) दस्तावेज़ Ex.A3 से पता चलता है कि गलती हुई थी मई 1982 के अंतिम सप्ताह में खोजा गया। अतः इस पर सहमति हुई त्रुटि को सुधारें, इसलिए पार्टियों ने वैसा ही किया · डी अधिनियम की धारा 26 के तहत एक सुधार। लिखित में द्वारा दायर मुकदमे में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल किया गया बयान प्रतिवादी क्रमांक 1, अनुच्छेद क्रमांक. 7 एवं 9 गलती को दर्शाता है और यह भी, सुधार. इस प्रकार, दस्तावेज़ उदा.ए-3 नहीं हो सकता इसे "विनिमय करने के समझौते" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसे केवल पढ़ा जा सकता है ई एक सुधार कार्य के रूप में, जो केवल द्वारा ही किया जा सकता था निपटानकर्ता, न कि प्रतिस्पर्धी दलों द्वारा।

(viii) संपत्तियों के संबंधित क्षेत्र पर विचार करना क्रमांक 22 और 23, अनुबंध निश्चित रूप से आयोजित किया जा सकता है एफ "अचेतन"।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सुविचारित राय पर हैं अपीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं। तदनुसार ही हैं बर्खास्त. कोई लागत नहीं.

सिविल अपील संख्या 2004 का 2184-2185

ये अपीलें हैं. उपर्युक्त द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया मुख्य मामलों में निर्णय अर्थात सी.ए. क्रमांक 2178-2179 दिनांक 2004। तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **हिमानी चतुर्वेदी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।